THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes, Sir. The guidelines pertain to River Valley Projects, Thermal Power Projects, Mining Projects Industries, Shipping and Harbour Projects and Development of Beaches.

(b) The guidelines deal with the environmental aspects that need to be considered during planning and implementation of development projects.

With respect to specific types of projects which require detailed Environmental Impact Assessment, the guidelines outline the factors which need to be addressed to. These are: meteorology and air quality, hydrology and water quality, occupational safety and health effects and impact on sensitive targets including flora and fauna.

The guidelines also enlist the aspects to be incorporated in the Environmental Management Plans for mitigation of adverse impacts.

बैंकों द्वारा राजस्थान में कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण

1067. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किन-किन योजनाओं के तहत कितने व्यक्तियों को कितनी धन राशि के ऋण बांटे गये हैं ।

(ख) ऋण प्राप्त करने के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा उनमें से कितने व्यक्तियों का चयन किया गया तथा अब तक उनमें से कितने व्यक्तियों को वास्तव में ऋणों का भुगतान कर दिया गया है तथा प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

(ग) क्या इस प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी बैंकों अथवा सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

(घ) बैंक ऋणों का लाभ उठाने वाले कमजोर वर्ग के व्यक्तियों में से पृथक्-पृथक् कितने व्यक्ति अल्पसंख्यक थे, कितने अनुसूचित जाति के थे तथा कितने पिछड़े वर्गों के थे ; और

(ङ) स्व-रोजगार योजना के अधीन कितने युवकों के चयन का लक्ष्य निश्चित किया गया था, वास्तव में कितनों का चयन किया गया तथा चुने गये व्यक्तियों में से अब तक वास्तव में कितने व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋणों का भुगतान कर दिया गया हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री एडूवर्डो फलेरियो (क) से (घ) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक राजस्थान सहित सभी राज्यों में नियमित आधार पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान कर रहे हैं । इन बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दें । इनमें अन्य अग्रिमों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये जाने वाले अग्रिम भी शामिल हैं । दिसम्बर, 1984, 1985 और 1986 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राजस्थान में कमजोर वर्गों के नाम बकाया अग्रिमों का ब्यौरा निम्नलिखित था :—

	कमजोर वर्ग		अनुसूचित जातियों/अनुसूचितजन-जातियों का हिस्सा	
	खाते	राशि	खाते	राशि
दिसम्बर 1984	564754	157.42	235011	73.8
दिसम्बर 1985	651999	217.83	271210	83.8
दिसम्बर 1986	766519	257.45	323101	112.21

(ङ) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 5150 के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1987-88 के दौरान 5579 व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया ।

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा किया जाना

1068. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ था और उस समय इसके निर्माण के लिए कितने व्यय का अनुमान लगाया गया था, उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और भविष्य में परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इसके निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार और घटिया सीमेंट के प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस नहर द्वारा राजस्थान में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की जा रही है अथवा भविष्य में की जाएगी; और

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की मरुभूमि में सिंचाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई बड़ी सिंचाई परियोजना बनाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राजस्थान नहर (अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना) पर कार्य 1958 में शुरू हुआ था । वर्ष 1957 में जल-प्रवाह आपूर्तियों से केवल सिंचाई की परिकल्पना करते हुये परियोजना की अनुमानित लागत 61.48 करोड़ रुपए थी । बाद में, परियोजना के क्षेत्र को संशोधित किया गया था और परियोजना को निरन्तर सिंचाई प्रदान करने के वास्ते जल भंडारणों का निर्माण करने का विचार किया गया था । परियोजना को राज्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा ब्लाक अनुदान तथा ऋण प्रदान किये जाते हैं । मार्च, 1988 तक, इस परियोजना पर 603.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है । वर्ष 1988-89 के लिए राज्य योजना में 60 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । तथापि, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान की दृष्टि से, परियोजना को अब तक निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है :-

सहायता	मार्च, 1988 तक	प्रावधान 1988-89
	(करोड़ रुपयों में)	
1. अग्रिम योजना सहायता	45.00	—
2. सीमा क्षेत्र विकास अनुदान	15.00	21.00 (10 करोड़ (रुपए निर्मुक्त किए गए)
3. सूखा सम्बन्धी राहत	9.00	11.00

परियोजना के जल मार्ग घटक भी कमान क्षेत्र विकास कार्य के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं । अब तक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित राज्य में परियोजनाओं के लिए 87.50 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं । राज्य सरकार ने नहर कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक 790 करोड़ रुपए की और राशि होने का अनुमान लगाया है ।

(ख) परियोजना पर कार्य की कोटि के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हुई हैं । इन